TIER 2

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (USCIRF) अमेरिकी संघीय सरकार का एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय निकाय है जो विदेश में धार्मिक या आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर निगरानी रखता है। इसकी स्थापना 1998 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा की गई थी, USCIRF विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करता है एवं राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है। USCIRF यू.एस. विदेश मंत्रालय से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। 2019 की वार्षिक रिपोर्ट कमिश्नर और पेशेवर स्टाफ द्वारा जमीनी तौर पर हुए इन उल्लंघनों को दस्तावेजीकृत करने के एक वर्ष के काम के समापन और अमेरिकी सरकार को स्वतंत्र नीतिगत अनुशंसाएं देने को दर्शाती है। 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक के मामले शामिल हैं, हालांकि कुछ मामलों में इस समयावधि के पहले और बाद घटी घटनाओं को भी शामिल किया गया है। USCIRF के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट यहां देखें, या USCIRF से सीधे 202-523-3240 पर संपर्क करें।

भारत

मुख्य निष्कर्ष: 2018 में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां निरंतर खराब हुई हैं। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है, जहाँ हर धर्म के धार्मिक समुदाय पनपे हैं। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और देश की स्वतंत्र न्यायपालिका ने अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अपने अधिकार क्षेत्र के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा प्रदान की है। फिर भी, धार्मिक स्वतंत्रता का यह इतिहास हाल के वर्षों में बढ़ते बहिष्कारवादी अतिवादी मुद्दों ने - जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उपद्रव को प्रोत्साहन और सरकारी अनुमति भी शामिल है - गैर-हिंदू और निम्न जाति के हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ धमकी, और उत्पीड़न भरे हिंसा के एक अहंकारी और चल रहे अभियान को बढ़ावा दिया है। सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। 2018 में, लगभग एक तिहाई राज्य सरकारों ने गैर-हिंदुओं और दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और/या गौहत्या विरोधी कानूनों को तेजी से लागू किया। इसके अलावा, हिंसा से जुड़े गौ-रक्षा दल मुख्य रूप से मुस्लिमों और दलितों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें से कुछ पीढ़ियों से कानूनी रूप से डेयरी, चमड़े या गोमांस का व्यापार कर रहे हैं। जबरन या प्रेरित धार्मिक रूपांतरण के आरोपों के तहत ईसाइयों के साथ उपद्रव भी किया गया। गौहत्या या जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करने वाले मामलों में, पुलिस जाँच और अभियोजन अक्सर पर्याप्त रूप से नहीं किये गए। विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पंजीकरण पर नियमों को धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति राज्य से राज्य नाटकीय रूप से भिन्न रही, कुछ राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अपेक्षाकृत खुलापन और मुक्त माहौल जारी रहा, जबकि अन्य - अगर अपने दम पर लिये - धार्मिक स्वतंत्रता के "व्यवस्थित, गतिशील, अहंकारी" उल्लंघन थे। 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने

कुछ राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती परिस्थितियों को उजागर किया, इस निष्कर्ष के साथ कि कुछ राज्य सरकारें धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रही और कुछ चरम उदाहरणों में, सांप्रदायिक हिंसा में लिप्त अपराधियों को दंड मुक्त किया जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बमुश्किल ही उपद्रव को कम करने वाले बयान दिए, और उनकी राजनीतिक पार्टी के कुछ सदस्यों का हिंदू चरमपंथी समूहों के साथ जुड़ाव रहा और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया। हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर हमला-पीड़ितों को न्याय नहीं दिया गया, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ स्वीकारे गए रिपोर्ट किए गए नए अपराध पर्याप्त रूप से न तो लगाए गए न मुकदमा चलाया गया। भारत की मूल जनसंख्या इन मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमता को जटिल और सीमित दोनों करती है।

इन मुद्दों के आधार पर, 2019 में USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में संलग्न रहने या सहन करने के लिए फिर से अपने टीयर 2 में भारत को रखा है जो "विशेष चिंता का देश", या CPC, के रूप में नामित होने के लिए "व्यवस्थित, चल रहे, प्रबल" मानक के कम से कम एक तत्व को पूरा करता है। जबकि भारत सरकार ने बार-बार USCIRF के भारत में प्रवेश से इनकार किया है, आयोग खुले तौर पर और खुलकर सरकार के साथ जुड़ने के अवसर का स्वागत करता है - जिसमें USCIRF प्रतिनिधिमंडल के भारत आने का मौका भी शामिल है - साझा मूल्यों और हितों पर चर्चा करने के लिए, जिसमें धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता और संबंधित मानव अधिकार के अंतरराष्ट्रीय मानक शामिल हैं।

अमेरिकी सरकार को सिफारिशें

- भारत सरकार पर एक USCIRF प्रतिनिधिमंडल को भारत की यात्रा करने और भारत में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हितधारकों के साथ मिलने की अनुमति देने के लिए दबाव डालना;

- धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधों से निबटने के लिए एक बहुवर्षीय रणनीति बनाने के लिए मोदी सरकार के साथ काम करनाः
    - भारतीय सरकार से उन सरकारी अधिकारियों व महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने की अपील करना जिन्होंने सार्वजनिक भाषणों या लेखों के जरिए धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काई है, जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जुलाई 2014 में अनुशंसा की है;
    - धार्मिक हिंसा के मामलों को रोकने और दंडित करने के लिए राज्य और केंद्रीय पुलिस के प्रशिक्षण और क्षमता को मजबूत करना, साथ ही पीड़ितों, गवाहों और पूजन स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों की रक्षा करना;

- राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को प्रोत्साहित करना; तथा
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधों के लिए अभियोगों की दर बढ़ाने के लिए राज्य अभियोक्ताओं के साथ काम करने हेतु कानून मंत्रालय की सहायता करना;

- धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा, और धार्मिक समुदायों, स्थानीय सरकारी नेताओं और पुलिस के साथ बातचीत से प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर यात्राओं के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानव अधिकारों पर अमेरिकी दूतावास का ध्यान बढ़ाना; तथा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी और मानवाधिकार समूहों को लक्षित करने के लिए विदेशी योगदान नियमन अधिनियम का उपयोग भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं किया जाता है भारतीय केंद्र सरकार की वकालत करना, और राज्यों पर धर्मांतरण विरोधी और गौहत्या विरोधी कानूनों के लिए यही करने का दबाव डालना।

पृष्ठभूमि

भारत

पूरा नाम: भारत गणराज्य

सरकार: संघीय संसदीय गणराज्य

जनसंख्या: 1,210,193,422

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धर्म/विश्वास: धर्म-निरपेक्ष संविधान

धार्मिक जनांकिकी*:

79.80% हिंदू

14.2% मुस्लिम

2.3%ईसाई

1.7%सिख

0.7% बौद्ध

0.4% जैन

0.7% अन्य (पारसी, यहूदी, बहाई, एवं जनजातीय धर्मों सहित)

0.2% धर्म निर्दिष्ट नहीं

*अनुमान भारत की 2011 की जनगणना से संकलित (15वीं जनगणना)

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत न केवल दक्षिण एशिया में अग्रणी है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान के साथ एक अद्वितीय शक्ति भी है। इसकी नींव लोकतंत्र की एक जीवंत और अबाधित संसदीय प्रणाली द्वारा सशक्त है, जिसमें एक सक्रिय और स्वतंत्र न्यायपालिका और एक संघीय संवैधानिक प्रणाली शामिल है जो केंद्र सरकार की कुछ शक्तियों को सीमित करती है और राज्यों को नीति निर्धारक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा देती है।

पिछले एक दशक में, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्थितियां खराब हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), संघ परिवार, और विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के बहुमुखी अभियान ने गैर-हिंदुओं या निम्न-जाति के हिन्दुओं में अलगाव पैदा करने के लिए धार्मिक हिंसा और उत्पीड़न बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अभियान ने जिन लोगों को निशाना बनाया, उनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और निम्न-जाति के हिंदू शामिल हैं - जो हिंसा या धमकी से लेकर राजनीतिक सत्ता के नुकसान, विघटन की बढ़ती भावनाओं और शिक्षा, आवास और रोजगार पहुँच पर सीमितता की चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि शिक्षा, आवास और रोजगार के लिए सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है, जो ऐतिहासिक रूप से असंतुष्ट समूहों, विशेष रूप से निम्न-जाति के हिंदुओं की सहायता के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, कुछ ने इसकी प्रभावकारिता और कार्यान्वयन में निष्पक्षता पर सवाल उठाया है।

2017 में, भारतीय सरकार की आपराधिक आंकड़े एकत्रित करने वाली एजेंसी, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने बताया कि 2016 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, 2018 में, अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने उपद्रव या अपहनन पर अधिक श्रेणियों को शामिल करने में विफल रहने के लिए NCRB की कार्यप्रणाली की आलोचना की। तदनुसार, NCRB ने लगभग 30 नई अपराध श्रेणियों पर डेटा एकत्र करने के लिए अपनी 2018 रिपोर्ट में देरी की, जिसमें घृणा अपराध, अपहनन और नकली समाचारों पर आधारित अपराध शामिल होंगे।

2018 में, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बचाव और सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। फरवरी 2018 में, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने संसद को सूचित किया कि 2017 के दौरान 822 सांप्रदायिक झड़पों में 111 लोग मारे गए और 2,384 घायल हुए (जबकि पिछले साल 703 घटनाओं में 86 लोग मारे गए और 2,321 घायल हुए)। सकारात्मक रूप से, दिसंबर 2018 में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक हमलों की संख्या में 2017 के उच्च स्तर से 2018 में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। स्वतंत्र घृणा अपराध निगरानी सेवाओं ने बताया कि 2018 में 90 से अधिक धार्मिक-आधारित घृणा अपराध हुए, जिससे 30 मौतें हुईं और कहीं ज्यादा घायल हुए।

इसके अलावा, संस्थागत चुनौतियां धार्मिक स्वतंत्रता सहित सभी मुद्दों की प्रगति को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के सामने एक बड़ा काम है जिसमें बढ़ती आबादी और उनकी

क्षमता, प्रशिक्षण, और वित्त पोषण की दीर्घकालीन जरूरतों ने पुलिस और अदालतों को व्याकुल कर दिया है। इसके अलावा, आय में बढ़ती असमानता ने और अधिक भारतीयों को गरीबी में धकेला है और कुछ विशेष धार्मिक व सामाजिक अल्पसंख्यकों के लिए असमानता की ऐतिहासिक परिस्थितियों को और अधिक खराब किया है।

धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2018

सकारात्मक परिवर्तन: 2018 में धार्मिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों में अवनति के बावजूद, कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। कुछ सरकारी निकायों ने देश में बढ़ रही असहिष्णुता से लड़ने के लिए प्रयास किए हैं, जिसके कारण गृह मंत्री सिंह के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में सांप्रदायिक हिंसा में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सक्रिय और स्वतंत्र न्यायपालिका ने इस वर्ष ऐसे अनेक मामले निबटाए हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने उपद्रव रोकने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को बुलाया और जून 2018 में केंद्र और राज्य की केंद्र सरकारों को 11 सूत्री योजना का पालन करने के लिए एक अनुवर्ती कॉल जारी किया, जिसमें अपराध पीड़ितों से घृणा करने के लिए मुआवजा, अभियोगों की तेजी से ट्रैकिंग, सांप्रदायिक मुद्दों और अन्य प्रावधानों से निपटने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना शामिल है। निचली अदालतों ने भी उपद्रवी सदस्यों पर मुकदमा चलाने में कुछ प्रगति की; उदाहरण के लिए, मार्च 2018 में पूर्वी राज्य झारखंड की एक अदालत ने जून 2017 में 11 लोगों को एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

2018 में, सरकार ने अपने बजट का अधिकांश अल्पसंख्यक विकास परियोजनाओं में निवेश किया। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अपने बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की, और यह बताया गया कि सभी नई अल्पसंख्यक विकास परियोजनाओं ने संयुक्त रूप से अल्पसंख्यक मामलों के लिए 62 प्रतिशत वृद्धि का गठन किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - जो 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में बनाया गया और जिसके सदस्य सरकार नामित हैं - ने उन घटनाओं का दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट करना जारी रखा जिनमें राजनेता और सरकारी अधिकारी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए सार्वजनिक रूप से उकसाने में लिप्त थे।

हिंदुत्व/हिंदू अतिवादी समूहों की भूमिका: भारत के विभिन्न राष्ट्रवादी समूहों ने हिंदुत्व या हिंदूवादी विचारधारा का विस्तार किया, जिसमें तीन स्तंभ हैं- सामान्य राष्ट्र, जाति और संस्कृति- और एक बहुधा बहिष्करण राष्ट्रीय रीति का आधार बनाते हैं एकमात्र हिंदुओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इन समूहों से संबंधित व्यक्तियों और उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के कारण विचार व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। फिर भी, हिंदुत्व आंदोलन के भीतर उदारवादी और अतिवादी दोनों ताकतें मुस्लिम आबादी में 1951 में राष्ट्रीय जनसंख्या के 10 प्रतिशत हिस्से से 2011 में 14 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करती हैं, जो कि उनके विचार में बढ़ते मुस्लिम समुदाय के खिलाफ "शमन" की आवश्यकता को दिखाती है। जहाँ कुछ हिंदुत्व समूह राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिंदू

सिद्धांतों का अधिक प्रभाव चाहते हैं, बहुत से चरम तत्वों ने कहा है कि वे सभी गैर-हिंदुओं को निष्कासित, मारे गए या हिंदू धर्म में परिवर्तित होते देखना चाहते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ सदस्यों का हिंदू चरमपंथी समूहों के साथ जुड़ाव है और उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में भेदभावपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, 2018 में, राज्य-स्तरीय भाजपा सदस्य टी. राजा सिंह पर पुलिस द्वारा अभद्र भाषा के उपयोग के बाद आरोप लगाया गया था कि "प्रत्येक हिंदू को लाठियों [क्लबों] जैसे हथियार रखने चाहिए और यदि अन्य समुदाय कुछ भी गलत कहे तो उन के सदस्यों पर हमला कर देना चाहिए।"

हिंदुत्व समूहों का प्रभाव राजनीति और सरकार से परे है। उदाहरण के लिए, हिंदुत्व समूहों ने धार्मिक स्कूलों-जो अक्सर गैर-सरकारी निजी शैक्षिक प्रणालियों में असहिष्णु धार्मिक विचारधारा सिखाते हैं-के दायरे और आकार को बढ़ाकर लगभग चार मिलियन छात्र कर लिया, और पब्लिक स्कूलों में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों को वितरित करने का प्रयास किया है। कुछ समूहों में छात्र युवा विंग हैं, जैसे कि RSS के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), जिन्होंने अपने धर्मनिरपेक्ष या गैर-हिंदू सहपाठियों को चुप कराने के लिए कॉलेजों में डर और हिंसा का इस्तेमाल किया और उनके दृष्टिकोण को चुनौती देने वाली घटनाओं को बंद कर दिया।

सामान्य तौर पर, संघीय और राज्य दोनों सरकारों ने भड़काऊ भाषा के उपयोग की निंदा करने के लिए बहुत कम काम किया है, भले ही उसने हिंसा को उकसाया है। और कई शहरों का नाम -जैसे कि मुगल काल के दौरान दिए गए नामों में से फैजाबाद और इलाहाबाद- बदलने के लिए राज्य की कार्रवाई को भारतीय इतिहास में गैर-हिंदुओं के प्रभाव को मिटाने या कम करने के प्रयास के रूप में और आज भारत के मुसलमानों पर हमले के रूप में माना गया है।

धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून और जबरन धर्मांतरण: धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में एक व्यक्ति के विश्वास को दूसरे में बदलने का या किसी पर विश्वास न करने का अधिकार शामिल है। इस अधिकार में अभिव्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति की मान्यताओं को प्रकट करने की क्षमता शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं या संबद्धता को स्वेच्छा से बदलने के लिए मनाने के लिए प्रेरित करता है। भारत में, राज्य स्तर पर धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून बल, खरीद, प्रलोभन या धोखाधड़ी के आधार पर रूपांतरण पर रोक लगाते हैं; हालाँकि, कुछ में ऐसी व्यापक परिभाषाएँ होती हैं, जिनकी व्याख्या किसी भी तरह के रूपांतरण पर रोक लगाने के रूप में की जा सकती है, चाहे वह सहमति हो या न हो। धर्मांतरण विरोधी कानून सात राज्यों: ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में लागू हो गए हैं। 2018 में, USCIRF ने एक रिपोर्ट जारी की, *दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं*, जिसमें भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की प्रवृत्ति पर चर्चा हुई। कुछ राज्यों में, रूपांतरण में लिप्त व्यक्ति को स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करना होगा।

2018 में, मुख्य रूप से धर्मांतरण में लिप्त मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ रूपांतरण-विरोधी कानून लागू किए गए और धर्म की स्वतंत्रता या दूसरों के विश्वास, चर्चा, विचार और अंततः अन्य धर्मों में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। इसके अलावा, धार्मिक अल्पसंख्यक नेताओं और अनुयायियों को धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आड़ में धमकी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, मई 2018 में, अधिकारियों ने झारखंड के एक घर में समूह प्रार्थना कराने पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया, और पास ही में स्थानीय लोगों द्वारा ईसाई विवाह समारोह आयोजित कराने की शिकायत के बाद चार अन्य को गिरफ्तार किया गया। दो महीने बाद उसी राज्य में, 25 ईसाइयों को प्रेरित रूपांतरण के आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने एक ईसाई के घर पर एक समूह प्रार्थना करवाई थी। जहाँ नौ को रिहा कर दिया गया था, समूह के शेष सदस्यों को झारखंड के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोपित ठहराया गया और उनके आरोपों पर मुकदमा चलाने के दौरान उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था; रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक ये मामले चल ही रहे थे।

2018 में, हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने और इस्लाम में परिवर्तित करने वाले एक संगठित अभियान के भड़काऊ आरोपों के लिए मीडिया ने महत्वपूर्ण कवरेज समर्पित किया। मार्च 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के एक फैसले को अलग किया जिसमें हादिया नाम की एक महिला के विवाह को रद्द कर दिया गया था; मूल रूप से एक हिंदू परिवार से आई हादिया ने इस्लाम धर्म कबूला और 2016 में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। केरल उच्च न्यायालय ने माना कि वह एक संगठित जबरदस्ती अभियान के अधीन थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटा और संतुष्ट होने के बाद शादी का समर्थन किया और इस बात को बरकरार रखा कि उसने स्वतंत्र रूप से सहमति दी थी। हादिया मामले ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी जाँच एजेंसी को प्रेरित किया, ताकि महिलाओं को धर्मांतरण और शादी करने के लिए मजबूर करने के एक समन्वित अभियान के अस्तित्व की जाँच शुरू की जा सके। अक्टूबर 2018 में, NIA ने कई जाँच के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के अभियान का कोई सबूत नहीं था।

कुछ हिंदुत्व समूहों ने उन जन्मजात हिंदूओं को परिवर्तित करने की माँग की है जो "घर वापसी" रूपांतरण समारोहों के माध्यम से अन्य आस्था में वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे। कुछ मामलों में, इन रूपांतरण समारोहों में कथित रूप से बल या जबरदस्ती शामिल होती है; हालाँकि, यह पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है कि इस तरह के रूपांतरण स्वैच्छिक हैं या जबरन किए जाते हैं या नहीं। 2018 में ऐसे समारोहों की खबरें आती रहीं, हालांकि उनकी संख्या और प्रकृति की पुष्टि करना असंभव था। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2018 में, एक हिंदुत्व समूह पर आरोप लगाया गया था कि उसने उत्तर प्रदेश में एक दलित व्यक्ति पर शारीरिक हमला किया, जो हाल ही में हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गया था और रिपोर्टों के अनुसार, उसे हिंदू धर्म में वापस लौटने के लिए घरवापसी करने के लिए मजबूर किया। घटना के वीडियो, हालांकि कुछ हद तक अस्पष्ट हैं, दिखाते हैं कि आदमी के सिर से लोगों का समूह टोपी हटा रहा है और उसकी दाढ़ी शेव की जा रही है। अक्टूबर 2018 में, उत्तर प्रदेश में भी, एक

परिवार जो पीढ़ियों से मुस्लिम था, उसे कथित तौर पर हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया; जिसमें परिवार के 13 व्यक्ति शामिल थे।

गौहत्या कानून और निगरानी समूहः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, गौहत्या निषिद्ध है। इसके अनुसार, 29 में से 21 राज्यों ने विभिन्न प्रकार से गौहत्या को निषिद्ध घोषित किया है, जिसमें छह माह से लेकर 14 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। 2005 से, सर्वोच्च न्यायालय ने गौहत्या कानूनों की संवैधानिकता को स्वीकार किया है। 2018 में, अनेक राज्य सरकारों ने गौहत्या के लिए सजा को बढ़ाने हेतु अपने कानूनों में परिवर्तन किया है। जहाँ भारत में गौहत्या पर प्रतिबंध का एक लंबा इतिहास है, "गौ-रक्षा" उपद्रव एक नई घटना है, और ऐसे समूहों ने मई 2015 के बाद से 100 से अधिक हमले किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 44 मौतें हुईं और लगभग 300 घायल हुए। अकेले 2018 में, गौ रक्षा हिंसक भीड़ ने कम से कम 13 लोगों की जान ले ली और 31 घटनाओं में 57 को घायल कर दिया। संदिग्ध गौ हत्यारे को सार्वजनिक रूप से पीटकर या हत्या कर, न केवल यह भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है, बल्कि अक्सर वे दुग्ध उद्योग में लगे उन लोगों को भी परेशान करते और धमकाते हैं जिनके गौहत्या से कोई संबंध नहीं हैं। जुलाई 2018 में, राजस्थान में रकबर खान नाम के एक डेयरी किसान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जहाँ उसकी मृत्यु का विवरण मंडित करना जारी है, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस स्थानीय भीड़ के साथ मिलीभगत कर रही थी या सीधे इसमें शामिल थी। दिसंबर 2018 में, उत्तर प्रदेश में एक अन्य घटना में, एक शख्स ने गाय के शव मिलने पर पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह और एक अन्य पीड़ित की हत्या कर दी। जवाब में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीड़ का हमला एक दुर्घटना था और आम तौर पर उनके राज्य में उपद्रवी हत्या से इनकार किया जाता है।

जुलाई 2018 में भीड़ की हिंसा और गाय की हिंसा पर सुनवाई करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह असाधारण और गैर-कानूनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कानून बनाए, खासकर जब उनके कार्यों से घृणा अपराध होते हैं। सत्तारूढ़ - जिसने राज्य सरकारों को भीड़ की घटनाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया था - मवेशियों के वध, डेयरी फार्मिंग और गोमांस की खपत के लिए मुसलमानों के खिलाफ सतर्कता के बारे में अदालत में याचिकाओं के जवाब में आई थी।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराध और हिंसा वृद्धि: धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर निर्देशित घृणा अपराध और हिंसा वृद्धि 2018 में प्रचलित खतरे बने रहे। अप्रैल 2018 में, पश्चिम बंगाल में एक वार्षिक हिंदू त्योहार के दौरान, मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक हिंसा का एक उदाहरण जहाँ हिंदुत्व चरमपंथियों ने मुसलमानों को ताना मारा और मुस्लिम विरोधी बयानबाजी का इस्तेमाल किया। सांप्रदायिक झड़पों के दौरान कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कथित तौर पर भाजपा के सदस्यों के लिए संभावित लिंक की जाँच की, हालांकि मामला रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक जारी है।

इसके अलावा, ईसाइयों ने पिछले वर्ष भर अपनी सुरक्षा के खतरे की सूचना दी है, साथ ही साथ सीधे उनकी धार्मिक पहचान से संबंधित बढ़ते भेदभाव और अनुचित उपचार की भी। उदाहरण के लिए, ईसाई चर्चों से जुड़े विभिन्न अनुसंधान समूहों ने देश भर में, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ हाल के दशकों में ईसाई समुदाय का विकास हुआ है, नफरत फैलाने वाले भाषणों और देश भर में ईसाइयों के खिलाफ घृणा अपराधों में वृद्धि देखी। अगस्त और सितंबर 2018 के दौरान, अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में कई ईसाई पादरी, चर्च सेवाओं और प्रार्थना सभाओं के दौरान गिरफ्तार किए, जहाँ उपद्रव किया गया और दूसरों को धमकी दी गई। गिरफ्तार किए गए कुछ पादरी कथित रूप से धर्मांतरण के आरोपी थे। अक्टूबर 2018 में एक साथ हमलों के एक सिलसिले में, हिंदुत्व चरमपंथियों ने तमिलनाडु राज्य में चार चर्चों के खिलाफ धमकी जारी की। चर्च के उपासक सार्वजनिक रूप से घृणा फैलाने वाले भाषण, उनकी चर्च संरचनाओं पर हमले और चर्च के नेतृत्व को जारी खतरों के अधीन थे। दिसंबर 2018 में, एक भीड़ ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक छोटे से सामुदायिक चर्च पर हमला किया, जिससे क्रिसमस से ठीक पहले कई लोग घायल हो गए।

NGO पंजीकरण: जब से 2010 में 1976 के फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA)को नवीनीकृत किया गया है, तब से अनेक अंतरराष्ट्रीय मिशनरी और मानवाधिकार संगठनों को भारत में कार्य करने से रोक दिया गया है। कानून के संशोधन के अंतर्गत, सरकार अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषित ऐसे किसी भी NGO को बंद कर सकती है जो "राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों" में लगे हैं। सरकार ने 2014 से हजारों NGO को बंद करने में इस धारा का उपयोग किया है;कुछ रिपोर्टों के अनुसार 20,000 NGO को कार्य करने के लिए लाइसेंस देने या कार्य जारी रखने से इन्कार कर दिया गया। जिस प्रक्रिया से NGO को प्रमाणन के लिए आवेदन करना होता है, उसमें पारदर्शिता का अभाव होता है, और जिन NGO को परिचालन लाइसेंस से वंचित किया जाता है, वे अक्सर इनकार के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। NGO को अक्सर राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया, हालांकि, गैर-हिंदू धार्मिक संगठनों को भी निशाना बनाया गया था। नवंबर 2018 में, भारत सरकार ने माँग की कि 1,775 संगठन पिछले छह वर्षों में विदेशी धन का उपयोग प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए और स्पष्टीकरण प्रदान करें; इन संगठनों में कई गैर-हिंदू धार्मिक समूह शामिल हैं, कुछ हिंदू ट्रस्ट हैं जो प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन करते हैं, और धर्मनिरपेक्ष मानवाधिकार समूह हैं। दक्षिण एशिया में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं पर USCIRF की 2018 की रिपोर्ट और 2018 कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में FCRA के प्रभाव का वर्णन किया गया है।

हिंदू आबादी में से कुछ-जिनमें कुछ हिंदुत्व के चरमपंथी शामिल हैं- ईसाई मिशनरियों का मानना है कि दलितों को विशेष रूप से धमकी दी जा रही है, क्योंकि भारत में लगभग 200 मिलियन दलित हैं। कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह सामूहिक रूप से धर्मांतरण का डर था, जिसके कारण 2017 में कम्पैशन इंटरनेशनल, एक यू.एस.-आधारित ईसाई धर्मार्थ संगठन को बंद कर दिया गया, जिसने लगभग 150,000 भारतीय बच्चों को सेवाएं प्रदान कीं। कम्पैशन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बंद ही रहा; यह भविष्य में भारत में परिचालन फिर से खोलने की

उम्मीद करता है, हालांकि FCRA को ईसाई समूहों के खिलाफ लागू करने के तरीके पर विचार करते हुए यह मुश्किल साबित हो सकता है।

बड़े-पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के लिए निरंतर माफी: बिना उचित जवाबदेही या पुनर्मूल्यांकन के भारत भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के कई उदाहरण वर्षों बाद भी अनसुलझे हैं। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों की जाँच और अभियोग बहुत बार अप्रभावी या अनुपस्थित रहे हैं। इसके अलावा, पीड़ितों ने शिकायत की है कि सरकार ने नष्ट हुए मोहल्लों, मकानों और पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान नहीं की है।

बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को दोबारा होने से रोकने के लिए सरकार ने भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संस्थानों के अलावा तथ्य-खोज आयोगों ने इस तरह की हिंसा के सामान्य लक्षणों और कारणों का उल्लेख किया है, जिनमें राजनेताओं या धार्मिक नेताओं द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को उकसाना शामिल है। फिर भी उन सामान्य विशेषताओं और कारणों को संबोधित करने में या ऐसी हिंसा जिसने दोष की संस्कृति में योगदान दिया के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकामी रही है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला, इन संघर्षों की स्थायी प्रकृति का उदाहरण देता है। 1992 में, हिंदुत्व समूहों ने बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के बाद, लगभग 2,000 लोगों ने महीनों के दंगों के बाद अपनी जान गंवा दी। 2018 में, राजनेताओं और अन्य लोगों ने मस्जिद के खंडहर पर एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए नए सिरे से कॉल के रूप में यह तनाव जारी रखा; 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साइट के संबंध में कई दलीलें सुनीं।

असम और नागरिकता: 1951 में, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की स्थापना की गई थी। NRC सभी पंजीकृत भारतीय नागरिकों पर नज़र रखने का एक तरीका था, क्योंकि असम एक सीमावर्ती राज्य है, जिसकी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और एक लगातार बदलती प्रवासी आबादी है। 2015 में, 1951 के बाद पहली बार NRC को अपडेट करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई। 24 मार्च 1971 के बाद किसी का भी जन्म हुआ, उसे भारतीय नागरिकता के दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं। जुलाई 2018 में, भारत सरकार ने NRC के लिए एक ड्राफ्ट अपडेट जारी किया, जिसने लगभग चार मिलियन लोगों को इस तरह के दस्तावेज प्रदान करने में उनकी कथित अक्षमता के कारण रजिस्टर से बाहर कर दिया। उस समय से, ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों ने सैकड़ों हजारों आपत्तियां दर्ज की हैं। अंतिम NRC सूची जुलाई 2019 में जारी होने की उम्मीद है; भय और/या अपेक्षा यह है कि उस सूची में किसी को भी राज्य से बाहर का नहीं माना जाएगा बल्कि उसे विदेशी माना जाएगा।

व्यापक चिंताओं को उठाया गया है कि NRC अपडेट भेदभाव करने और/या मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, और यह कि सत्यापन प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों को दिया गया विवेक ड्राफ्ट सूची से बाहर किए जाने वाले कथित विदेशियों की पहचान करने में एक दुर्व्यवहार होगा। कुछ के लिए, ड्राफ्ट

से चार मिलियन लोगों के बहिष्कार से NRC ने उन चिंताओं की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष रूप से चार जून 2018 के संयुक्त पत्र - जिसमें धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर विशेष तालमेल शामिल है - ने स्पष्ट किया कि नागरिकता रजिस्ट्री ने "असम में बंगाली मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच चिंता और परेशानी बढ़ा दी हैं, जो लंबे समय से वहाँ हैं जिनसे अपनी नागरिकता साबित करने के आवश्यक दस्तावेज रखने के बावजूद उनकी कथित स्थिति के कारण विदेशियों के रूप में भेदभाव किया गया।" संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने एक दिसंबर 2018 के बयान में अपनी चिंताओं को दोहराया, जिसमें कहा गया कि उस समय सटीक बहिष्करण अज्ञात थे, वे "जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों" को लक्षित करने के लिए दिखाई दिए। विदेश विभाग ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद जारी भारत के लिए अपनी 2018 की मानवाधिकार रिपोर्ट में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के भयावह स्वरूप पर प्रकाश डाला।

संसद के लोकसभा ("निचले सदन") में, नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करने और पारित करने से मुसलमानों को निशाना बनाने की चिंता नागरिकता प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग बढ़ गईं जहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों को तब तक नागरिकता प्रदान की जाएगी जब तक वे मुस्लिम नहीं थे। फरवरी 2019 में, समीक्षाधीन अवधि के बाद, विरोध के बीच संसद के राज्य सभा ("ऊपरी सदन") में इस बिल को हटा दिया गया।

महिला और धार्मिक स्वतंत्रता: 2018 में, भारत में महिलाएँ और लड़कियाँ लगातार अंतर जातीय प्रेम हत्याओं, अंतर जातीय हिंसा, और धार्मिक कारणों से यौन हिंसा का निशाना बनती रही। कथुआ बलात्कार मामले के रूप में जानी जाने वाली 2018 की घटना में, आसिफ़बानो नामक एक आठ वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, और कश्मीर में उसके मुस्लिम खानाबदोश समुदाय के लिए एक संदेश और धमकी के रूप में हत्या कर दी गई। एक निजी मंदिर के पुजारी, उनके बेटे और एक विशेष पुलिस अधिकारी पर अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया; कई अन्य पुलिस अधिकारियों पर अपराधों को कवर करने का आरोप लगाया गया था। जहाँ कई लोगों ने युवा लड़की के बलात्कार और हत्या की निंदा की, कई अन्य लोगों ने आरोपित पुरुषों के समर्थन में आयोजन किया, जिसमें भाजपा के सदस्य भी शामिल थे।

वर्ष 2018 ने कुछ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की पूजा करने की क्षमता पर लगाए गए प्रतिबंधों की चर्चा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। सितंबर 2018 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि केरल में सबरीमाला मंदिर को वयस्क महिलाओं के लिए खोला जाए, जहाँ 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के लिए मंदिर में विशेष प्रवेश लंबे समय से प्रतिबंधित है। जवाब में, मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली महिलाओं पर शारीरिक हमला किया गया और अन्य लोग जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से मौत के खतरे सहित नफरत भरे संदेश मिले। जनवरी 2019 में लगभग 5 मिलियन महिलाओं ने सभी के लिए समान पहुँच के पक्ष में विरोध करने के लिए मंदिर के पास 385 मील की मानव श्रृंखला बनाकर रिपोर्टिंग अवधि के बाद, जनवरी 2019 में प्रतिवाद आंदोलन शुरू किया।

अमेरिकी नीति

भारत और संयुक्त राज्य ने पिछले कई दशकों में संबंधों को मजबूत किया है, अब भारत को भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक फोकल साझेदार के रूप में वर्णित किया गया है। कई दशकों से, संयुक्त राज्य और भारत ने लोकतंत्र के साझा मूल्यों और कानून के शासन और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, और आतंकवाद-विरोधी साझा हितों के आधार पर एक रणनीतिक संबंध बनाया है। U.S.- इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग को 2009 में लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से देशों ने आर्थिक विकास, व्यापार और ट्रेड, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-विरोधी और पर्यावरण जैसे कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि, मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर नहीं दिया गया है।

2017 में, जब प्रधान मंत्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, तो वह और राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और गहरा बनाने के लिए 2 + 2 संवाद बनाने पर सहमति व्यक्त की। सितंबर 2018 में 2 + 2 संवाद की उद्घाटन बैठक में, राज्य के सचिव माइकल आर पोम्पेओ और तत्कालीन रक्षा सचिव जेम्स एन. मैटिस ने बहु-मुद्दे समझौते के लिए शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारत की संयुक्त यात्रा की। जून 2018 में भारत की यात्रा के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में तत्कालीन राजदूत निक्की हेली ने उल्लेख किया कि संयुक्त राज्य और भारत दोनों धार्मिक स्वतंत्रता को कितना सम्मान देते हैं। इसी तरह, जब यह पूछा गया कि मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के यू.एस. और भारत के बीच 2 + 2 संवाद को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, तो दक्षिण और मध्य एशिया के उप सहायक सचिव एलिस वेल्स ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है।

2018 में, अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने धार्मिक उत्पीड़न और असहिष्णुता के बारे में धार्मिक प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा में शामिल होना और अंतर-वार्ता संवाद को बढ़ावा देना जारी रखा। दिसंबर 2018 में, निकट पूर्व और दक्षिण / मध्य एशिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों के वरिष्ठ सलाहकार नोक्स थैम्स ने भारत का दौरा किया और धार्मिक समुदायों के साथ मुलाकात की और पारस्परिक संबंधों पर चर्चा की।

2001 से, USCIRF ने जमीनी तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए भारत की यात्रा का प्रयास किया। हालांकि, 2001, 2009 और 2016 में - तीन भिन्न अवसरों पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा समर्थित अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार ने USCIRF प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने से इन्कार कर दिया।

अध्यक्ष तेनजिन दोरजी के व्यक्तिगत विचार:

जहाँ भारत को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, मैं भारत के धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के विचारों पर असंतोष व्यक्त करता हूँ, सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ हिंसा की अनुमति दी और प्रोत्साहित किया, और कुछ राज्य "व्यवस्थित, चल रहे, और धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में शामिल हैं।" भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक और न्यायपालिका प्रणाली के साथ एक खुला समाज है।

भारत एक महान सभ्यता है, और प्राचीन काल से वह बहुआस्तिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश रहा है। मैं एक तिब्बती शरणार्थी के रूप में 30 से अधिक वर्षों तक भारत में रहा और ज्यादातर भारत को सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखा और कभी-कभी अवर्णीय अंतरसंबंधी संघर्षों के कारण सबसे खराब। दुर्भाग्य से, धार्मिक विभाजन और सत्ता संघर्ष ने न केवल भारत और पाकिस्तान के विभाजन का नेतृत्व किया, बल्कि अक्सर धार्मिक स्वतंत्रता और त्रासदियों के गंभीर उल्लंघन में योगदान किया। इन मुद्दों के बावजूद, भारत एक बहुस्तरीय और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में मौजूद है। परम पावन दलाई लामा धार्मिक विविधता और सद्भाव और सम्मान और करुणा जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए भारत की बहुत प्रशंसा करते हैं, और सभी धर्मों और गैर-विश्वासों के बीच वैश्विक सद्भाव को पुनर्जीवित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खुद को प्रतिबद्ध किया है।

मैं ज्यादातर दो भारतीय राज्यों, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पला-बढ़ा। एक तिब्बती शरणार्थी - वहाँ सभी अल्पसंख्यकों में सबसे कमजोर अल्पसंख्यक - के रूप में भारत में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का अनुभव किया। तिब्बत के अंदर, कम्युनिस्ट चीन ने व्यवस्थित रूप से, कट्टरता से, और लगातार तिब्बती धर्म, भाषा, संस्कृति और पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। हालाँकि, भारत और भारतीय लोगों के पूर्ण समर्थन के कारण तिब्बती भाषा, धर्म और संस्कृति भारत में पनपती है। कई विद्वानों के प्रकाशनों में, मैंने इसकी बड़े पैमाने पर चर्चा की और एक तिब्बती अमेरिकी के रूप में, मैं अक्सर भारत का दौरा करता हूँ और वहाँ प्रचुर धार्मिक स्वतंत्रता और पारस्परिक सद्भाव देखता हूँ।

जैसा कि मैंने पिछले साल टिप्पणी की थी, कुल मिलाकर, मेरा मानना है कि भारत में धार्मिक सद्भाव मौजूद है। पिछले साल, बिहार के बुद्धपुर में, एक मुस्लिम गाँव ने अपने हिंदू परिवारों के लिए एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए भूमि और धन का दान किया, और पंजाब के एक गाँव में, एक हिंदू मंदिर ने पास में भूमि दान की, और हिंदुओं और सिक्खों ने अपने समुदाय के मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाने में मदद की। विशेष रूप से, पिछले साल हैदराबाद में, हिंदू प्रधान पुजारी सीएस रंगराजन एक दलित युवक आदित्य पाराशरी को अपने कंधों पर चिलकुर बालाजी मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में ले गए, और एक बड़ी भीड़ ने जय-जयकार की। संबंधित रूप से, लुधियाना हिंदू और सिक्ख समुदायों के पास नाथोवाल गाँव में एक पुरानी मस्जिद की मरम्मत में मदद मिली, और मुस्लिम और हिंदू समुदायों ने सिक्ख गुरुद्वारा मंदिर में काम करने में मदद की। इस गाँव के लोगों ने *टाइम्स ऑफ़ इंडिया* को बताया कि उन्होंने दीवाली, दशहरा, राखी, ईद, और गुरुपुरब जैसे वार्षिक बहु पर्व त्योहारों को एक साथ मनाया। ये कहानियाँ भारत की बहुभाषा सभ्यता, धार्मिक स्वतंत्रता और परस्पर सद्भाव को बयाँ करती हैं। मैं भारतीय नेतृत्व

और भारत के लोगों से दृढ़ता से धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और बहुसंख्यक लोगों के लिए एक जीवंत देश के रूप में भारत को बढ़ावा देने का प्रयास करने की अपील करता हूँ।

कमिश्नर अनुरीमा भार्गव के व्यक्तिगत विचार

भारत एक समृद्ध, बहु-आस्तिक, जीवंत लोकतंत्र है जो आयोग के साथ घनिष्ठ और रचनात्मक जुड़ाव रखता है। हालांकि, एक दशक से अधिक समय तक, आयोग को किसी भी आधिकारिक क्षमता में भारत के साथ बातचीत करने या जाने का अवसर नहीं दिया गया है। एक नई आयुक्त के रूप में, मैं आने वाले वर्ष में भारत के साथ आयोग के खुले और उत्पादक संवाद और मजबूत जुड़ाव की आशा करती हूँ।